म्यूनिसिपल काउंसिल, कोटा, राजस्थान।

बनाम.

द दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड

2 मार्च, 2001

[ न्यायमूर्ति वी. एन. खरे और दोराईस्वामी राजू, ]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959: धारा 104 (2)।

नगर शुल्क–धर्मदा कर–अधिसूचना ने नगर परिसीमा में माल के प्रवेश पर 'धर्मदा' कर का धन्यात्मक अधिसूचन किया। नगरपालिका को 'धर्मदा' कर वसूल करने से रोकने की याचिका खारिज की गई–लेकिन उच्च न्यायालय ने यह ठान लिया कि धारा 104(2) केवल ऐसे विधि–सरकारी करों से निपटने का सम्मति प्रदान करती है जैसे कि नगर शुल्क जो 'धर्मदा' कर जैसा शब्द काम आता नहीं। उच्च न्यायालय ने धराया कि 'धर्मदा' कर के रूप में लगाया और वसूल किया गया कर नगर शुल्क के रूप में है जिसे नगरपालिका को वसूल करने का अधिकार है। इसके अलावा, 'धर्मदा' कर का वसूलन दोहरे कराधान नहीं माना जाता। इसलिए, 'धर्मदा' कर का वसूलन वैधानिक है–भारतीय संविधान, 1950, अनुभाग 52 सूची ।। सातवीं अनुसूची।

शब्द और वाक्यांशः

" दोहरा कराधान "का अर्थ।

अपीलार्थी–नगरपालिका ने "धर्मदा" कर के रूप में वसूलन करने का प्रयास किया, जो प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा आयातित मालों पर लगाने का एक प्रकार का नगर शुल्क था, जो कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 104(2) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एक सूचना के आधार पर नगरपालिका सीमाओं में आयातित की जानेवाली सामग्रियों पर लगाने की कोशिश की। प्रत्यर्थियों ने एक याचिका दायर की जिसमें नगरपालिका से 'धर्मदा' कर को वसूल करने से रोकने की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय ने यह याचिका खारिज कर दी, जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय ने की। उच्च न्यायालय ने धारा 104(2) ने अभिनिर्धारित किया कि यह नगर शुल्क जैसे अनिवार्य करों को ही संबोधित करता है और 'धर्मदा' कर जैसी चीज़ें शामिल नहीं करता है और इसलिए राज्य सरकार को नगरपालिका को 'धर्मदा' कर वसूल करने का अधिकार नहीं था। इसलिए यह अपील दायर हुई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्णय दिया:

1.1. 1959 के राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 104(2) के अधिकारों का प्रयोग करके जारी किये गए अधिसूचना के नीति का उद्देश्य यह लगता है कि कुछ विशेष वर्ग या वस्तुओं पर नगर शुल्क का एक अतिरिक्त उभयन और वसूल करने का प्रावधान करना है, 'धर्मदा' या 'निर्खी' के नाम से, जो मांग के विशेष उद्देश्य या वस्तु की सूची को दर्शाने के रूप में है, लेकिन फिर भी उन वस्तुओं पर ही लगू होता है जो नगरपालिका के सीमाओं के

भीतर उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए लाई गई हैं, इसका इशारा देते हुए कि 'धर्मदा' और 'निर्खी' के नाम से वसूलन भी नगर शुल्क के रूप में है, कर लगाने का केवल और सिर्फ उस समय जब वस्तुओं और पशुओं का महल की सीमाओं के भीतर उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए होता है। (302–G–H; 303–A)

1.2. जब किसी कर के उत्पादन का विरोध किया जाता है, तो उसकी वैधानिक योग्यता का मुख्य रूप से संदर्भ करना आवश्यक हो सकता है सकारात्मक रूप से निर्धारित करने के लिए और इस मुद्दे का निर्णय करते समय कर की प्रकृति और विशेषत: स्थान निर्धारित करनी होगी। यह भी न तो उचित रूप से स्वाभाविक है कि एक बार यह तय हो गया है कि संघनित विधायिका को कर लगाने की शक्ति है, तो कर को लगाने के उद्देश्य का उल्लेख किया जाने का कोई महत्व नहीं है और यह भी कोई महत्व नहीं रखता है कि शक्ति का व्यय करने के लिए एक गलत कारण दिया गया है। (303–B·C)

1.3. उन नामों या चुनौतियों को न की तात्पर्यिक रूप से चुना गया है जो उधारण को नामित करने के लिए है, जो वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण या निर्धारक नहीं है, अधिकार या विधायन करने के लिए या उपकरण करने के लिए। वास्तविक रूप से देखा जाना चाहिए कि उधारण की सार–सारणी या वास्तविक प्रकृति और स्वभाव क्या है, जो निर्णय किया जाना है, उपकरण और उधारण के घटना और उधारण के अंश के संदर्भ में। जो उधारण लगाने और वसूल करने की कोशिश की जाती है 'धर्मदा' केवल उपभोग, उपयोग या वहां बिक्री के लिए नगरपालिका सीमाओं के भीतर लाई गई सामग्री पर है, उसका वास्तविकता, वास्तविकता और सार यह केवल एक 'नगर शुल्क' है जो कानूनिक रूप से परिस्थितियों को पारित करने के उद्देश्य से है, जो कि नगरपालिका बोर्ड को यस्त्रिय निर्धारित सार्वजनिक दानी उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए वाधिक रूप से किया गया है और अधिनियम की धाराओं 101 और 102 में शामिल विश्वास अनुसरण करते हैं।बस यह अभियान है कि यह एक भिन्न नाम से कहा जाता है (ज्यादा तब भी जब सातवें अनुसूची की सूची II के अनुभाग 52 में 'नगर शुल्क' शब्द स्वयं उपयोग नहीं होता है) इतिहासिक कारण या अधिसूचन के उद्देश्यों और प्रशासनिक आवश्यकताओं द्वारा इसका आलोचन करने के लिए नहीं किया जाता है कि निर्धारित उधारण की प्रकृति और स्वभाव या इसे कम, यदि कोई, नगरपालिका की सूची II के अनुभाग 52 के तहत विचित्रित नहीं करता।

धर्मदा' के वर्गीकृत शीर्षक तहत वसूल की गई करों का प्रयाप्त रूप से खर्च किए जाने का दावा किया जाता है कि विभिन्न दानी उद्देश्यों और सुधारात्मक योजनाओं और परियोजनाओं के लिए, इसे विधिकी अनुमति से विभागीकृत या 'विधिके संविदान के किसी भी धारणा के बिना नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई भी, वसूली के बाद राशि को खर्च करने में शामिल नियमितता या अवैधता को उधारण की दिशा में कोई असमान या अनुमान नहीं कर सकती है कि व्यक्ति की प्राधिकरण से विचार करने की पार्श्वगार उदार या सत्यापन कर सकती है, जो कि अपनी विधायिकी संघ के भीतर है और दिखाया नहीं गया है कि भारतीय संविधान के किसी भी विधानों का उल्लंघन किया गया है। [305–B–G।

बर्माशेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेलगांव बनाम बेलगांव बोरो म्युनिसिपालिटी, बेलगांव, AIR (1963) SC 906, 'जलंधर रबर गुड्स निर्माता संघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR (1970) SC 1589 और (मॉरिस) लेवेंथल बनाम डेविड जोन्स लिमिटेड, AIR (1930) PC 129, इस पर संदर्भित किया गया।

CIT (केंद्रीय), दिल्ली, नई दिल्ली बनाम बिजली कॉटन मिल्स (प्रा.) लिमिटेड, हाथरस, जिला अलीगढ़, [1979) 1 SCC 496, को अनुलिप्त ठहराया गया।

राजयपाल परिषद बनाम मद्रास प्रांत, AIR (1945) PC 98, उद्धरित किया गया।

हालांकि एक ही वस्तु की विभिन्न नामों से कर लगाना सामान्य अर्थ में 'दोहरा कर' है, इस विषय के विशेषज्ञ विस्तार का भी एक पक्ष राजस्व के पक्ष में है, क्योंकि विधायिका को एक या एक से अधिक कर या कर दरों का अधिकार देने का विचार किया गया है जिसे उधारण दिया गया है, और इन क्षेत्रों में राज्य को अपनी संज्ञान की राह चुनने की अनुमति दी जाती है और उसे कर या उधारण की विभिन्न किस्म या विधि और उद्देश्य और वसूली की रीति चुनने का अधिकार दिया गया है, केवल तब तक, जब यहां कोई निर्देश नहीं है संविधान या संघ की तत्व से जोड़ा गया है या विधायिका द्वारा स्वयं ऐसे एक वस्तु का होने का आदान–प्रदान करने से रोकता हैतब तक, किसी भी विकल्प को विकल्पित करने के लिए कोई दोष हो सकता है। जहाँ विभिन्न विधायिकाओं या प्राधिकरणों द्वारा कर लगाए जाते हैं या जहाँ दो में से केवल एक कर लगाना है या जब यह पूरी तरह विभिन्न उद्देश्यों के लिए है या जब यह सीधा रूप से नहीं, अपरिपक्व है, तो इसके लिए कोई क्षेत्र नहीं है दोहरा कर की कोई भी शिकायत करने के लिए। एक देश के संविधान या विधायिका ने विशेष रूप से निर्मित किसी भी अवरोध की अनुपस्थिति में, ऐसे लेवियों से बचने की इच्छा या आवश्यकता राज्य की जनता की नीति निर्माण और सार्वजनिक वित्तों का समायोजन करने के क्षेत्रों से संबंधित होने का आर्थिक 'विवेक' क्षेत्रों में संबंधित रही है और वैधानिक कोर्टों के लिए नहीं है,

जैन बीआईवीएस बनाम भारत संघ, ए आई आर (1970) एससी 778; एटी विंदर सिंघ बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर (1979) एससी 321; श्री कृष्ण दास बनाम टाउन क्षेत्र समिति, चिरगांव, [1990] 2 एससी 645 और राधाकिशन राठी बनाम अतिरिक्त कलेक्टर, दुर्ग, [1995] 4 एससी 309, इस पर संदर्भित किया गया है।

री: वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स, ए आई आर (1954) बॉर्न 261 और स्टीवन्स बनाम दर्बन रॉडरपोर्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड, (1909) 5 टैक्स कैस 402, सादृश्य किया गया।

उपरोक्त कर तीव्र, निश्चित और सकारात्मक शब्दों में है, जिसमें निश्चित घोषित उद्देश्य है जिससे कोई संदेह या कोई विवाद स्थापित नहीं होता है। चुनौती को अक्सर किसी भी विदित विवाद या किसी अभ्यास के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। विवाद के तहत विमूलन की दरें सूची के एक हिस्से के रूप में अधिसूचित की गई हैं और यह न किसी अलग या एक से अधिक अनुसूची द्वारा है और न किसी विभिन्न अवसर या समय पर, हालांकि यह देखा गया है कि कुछ वस्त्रित आइटम या वस्त्र विभिन्न शीर्षकों के तहत अंकित हैं जिसमें धर्मदा भी शामिल हैं, वे मेकेनिकल रिपीटिशन्स नहीं हैं, न तो उन्हें उनकी वर्गीकरण, अंकन या दरों के तहत से देखा जा सकता है जिसके द्वारा वास्तविक कर लगाने और वसूल करने के लिए आवश्यक उपाय या माप या मात्रा समभाव गया है। इसलिए, विभिन्न विभागों के तहत कुछ वस्त्र/सामग्रियों की दरों का अनेकता का प्रावधान स्वयं में यह नहीं कहेगा

कि वे 'दोहरा कर' के रूप में या 'दोहरा कर' के रूप में ठहराया जा सकता है और उच्च न्यायालय ने इस प्रकार की भ्रांति पर आधारित होकर धर्मदा के उद्देश्यों के लिए लगान को बुरा और अवैध ठहराया है।"

"सिविल अपील अधिकरण: नागरिक अपील संख्या 4152/1991।

राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 29.07.1991 S.B. CSA संख्या 20/1982 में पारित निर्णय और आदेश से

साथ ही सिविल अपील संख्याएँ 4153/91, 2994/1984 और 2842/1989।

अल्ताफ अहमद, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, डॉ. एम. सिंघवी, शांति भूषण, सुशील कुमार जैन, ए.पी. धमीजा, श्रीमती अंजली दोशी, सैफ महमूद, प्रशांत भूषण, संजीव कपूर, नरेंद्र कुमार वर्मा, पी.एस. सुधीर और के. जे. जॉन उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय  का निर्णय निम्नलिखित था:

न्यायमूर्ति राजू, , इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि 'धर्मदा' के रूप में देने और वसूल करने के लिए लगू होने वाले कर के प्रकार और विशेषता, जैसा कि यह प्रत्यर्थीओं के अनुसार कोटा नगर परिषद, राजस्थान राज्य, द्वारा 'ओक्ट्रॉई' के रूप में कहा जाता है, जो प्रत्यर्थी कंपनियों द्वारा उपयोग की गई वस्त्रों पर 'धर्मदा कर' के रूप में नहीं है, बल्कि उनके अनुसार, कोटा नगर सीमा क्षेत्र में आयातित। इस राज्य के इस हिस्से में इस कर के उत्थान का पात्र ट्रेस करना आवश्यक है।"

हमारे सामने प्रस्तुत अभिलेखों और सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि 1860 ई० में कोटा के वही शासक, संकल्प के आधार पर व्यापारियों द्वारा भी एक ऐसा भुगतान करने का इच्छुक था, कोटा नगर के 'नंदगांव' के व्यापारियों पर 'नंदगांव' (कोटा नगर का प्राचीन नाम) में 'धर्मदा' कर लगू करने का दावा किया, जैसे कि शासक द्वारा बनाई गई वह विधि के प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता अनुसार एक ऐसे कर को लागू किया गया। इस तरह लगाए गए 'धर्मदा' के दर सूची का कहना है कि यह 1894 तक जारी रही जब इसे 6.11.1894 को सम्मानित किया गया था नगरपालिका समिति के संकल्प से। इसे उत्तराधिकारी रूप से 1922 के 22.11.1922 को जारी किया गया था तथा इसे बाद में 1923 में संशोधित किया गया था। यह भी प्रकट होता है कि 1929 से पहले नगर शुल्क / धर्मदा के उपावर्जन मामले को कोटा राज्य के न्यायाधीश की न्यायालय  में दर्ज किया गया और कर विधि के अनुसार दंडनीय अधिकार भी माना गया कि इसे अपाराधिक अधिनियम के तहत दंडनीय कर्तव्य बताया जा सकता है। 1929 में, कोटा राज्य नगर शुल्क अधिनियम का अधिवास कहा गया कि नगरपालिका बोर्ड, कोटा द्वारा 'धर्मदा' का वसूल करने और लगान करने की अधिकार दिया गया था। 1959 में, राजस्थान नगरपालिकाएँ अधिनियम ने नगर शुल्क अधिनियम 1929 के संचालन को बचाया।

लिंग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के करों का आयातन करने के लिए कर योजना बनाई, जिसे धारा 104 में 'अनिवार्य कर' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और धारा 105 में इसके अलावा व्यक्त किया जा सकता है कि और करों के लिए प्रावधान किया जा सकता है, संपत्ति कर, आदि का कर लगाने के लिए। धारा 104, जैसा कि वह समय पर स्थित थी,

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्द्वारा प्रत्येक अनुशंसा में भारी और तिथि के अनुसार, हर नगरपालिका बोर्ड को अनुशंसित किया गया कि 'निम्नलिखित करों का आयातन करें, अर्थात– (

!) ..... ;

(2) ऐसी वस्तुओं और जानवरों पर आयात शुल्क जो नगरपालिका की सीमाओं में आने वाली हैं उन्हें वहाँ सभ्यता, उपयोग या वहाँ बिक्री के लिए।"

"अधिसूचनाएं जारी करने की बात करे तो यहाँ कहा जा सकता है कि भारत के संविधान के लागू होने के बाद, कई अधिसूचनाएँ समय–समय पर जारी की गईं जैसे, उदाहरण के लिए, अधिसूचना क्रमांक एफ.2(150)एलएसजी/50 दिनांक 21.8.1950; दिनांक 17.12.1951 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना; अधिसूचना संख्या एफ. 150 एलएसजी/60 दिनांक 1.2.1962। जो एक के बाद एक सक्रिय हुईं और पहले अधिसूचना को रद्द कर दिया।"

"बाद में यह देखा गया है कि सरकार ने विधायिका की धारा 104(2) के अंतर्गत 13.5.1968 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कोटा नगरपालिका परिषद को विभिन्न और विशेष उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए तीन उप–शीर्षों के तहत नगर शुल्क लगाने की अधिकार दिया गया था, अर्थात– (!) सही नगर शुल्क; (2) धर्मदा; और (3) निरखी, निम्नलिखित रूप में:–"

राजस्थान गजट

असाधारण

जयपुर, 13 मई 1968

अधिसूचना कर एफ.144(2) डी.एल.बी. 161: –

कोटा नगर परिषद के मौजूदा नगर शुल्क दरों की स्थिति को बहाल करते हुए, राज्य सरकार ने 1959 के राजस्थान नगरपालिकाएँ अधिनियम की धारा 104(2) द्वारा सौंपी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए (राजस्थान अधिनियम संख्या 38/1959) यहाँ निर्दिष्ट दरों पर सामान और जानवरों पर नगर शुल्क लगाया जाएगा जो कोटा नगरपालिका की सीमाओं में उपयोग, सेवन या बिक्री के लिए लाए गए हैं, उक्त तालिका के प्रकाशन की तारीख से:"

तालिका

| माल का नाम। | निर्धारित दर प्रति मात्रा |
|---|---|
| क्रमिक संख्या 1 से 101 तक | |

धर्मदा

I. अनाज, सभी प्रकार। 0.02 रुपये प्रति क्विंटल

सीरियल नंबर 18 तक

पशु और पक्षियों, आदि

सीरियल नंबर 19 से 31 तक

आग और ईंधन के रूप में सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाला सामान

सीरियल नंबर 32 से 40 तक

भवन और निर्माण सामग्री

सीरियल नंबर 41 से 49 तक

दवाएँ, रासायनिक पदार्थ, इत्र, सौंदर्य सामग्री, आदि

सीरियल नंबर 50

शहरनामा निरखी, कोटा नगर परिषद, कोटा

| | | |
|---|---|---|
| अनाज, सभी प्रकार | 1.00 | प्रति दो क्विंटल। |
| तिल का तेल | 0.01 | " |

XX XX XX

राज्यपाल के आदेश द्वारा

स्वाक्षर– पी.एन. सेठ

उप सचिव (प्रशासन)

अब हम वर्तमान मुकदमे के इतिहास और उन चरणों पर आकस्मिक करेंगे जिसने उपरोक्त अपीलों में इस महकमे को लाया है, खासकर C.A. संख्या 4152/91 के तत्वों के संदर्भ में। C.A. 4152/91 में प्रत्यर्थी कंपनी ने अधिक मुनसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नंबर 2, कोटा (दक्षिण), के न्यायालय में सिविल सूची संख्या 5117/79 दायर की, जिसमें प्रत्यर्थी ने अपीलीकर्ता के खिलाफ प्रतिबंधी राहत की मांग की कि वह कंपनी द्वारा आयातित किसी भी वस्तु पर किसी भी धर्मदा कर की मांग न करे या उसकी वसूली के लिए किसी अन्य प्रक्रिया को न अपनाए और अपीलीकर्ता को अपीलीकर्ता को उल्लिखित दान करने या वस्त्रों के आयात करने

के लिए किसी भी Dharmada कर लगाने का अधिकार न हो और इस प्रभाव में एक अनिवार्य स्थायिक प्रतिष्ठान की मांग की। प्रत्यर्थी कंपनी का दावा की आवश्यकता थी कि धारा 104(2) राज्य सरकार को समर्थन और उपभोक्ता बनाने की अनुमति देती है

और इस परिणामस्वरूप, अपीलीकर्ता को नगर शुल्क कर के लिए अधिकारित करती है, जो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची ।। के अनुमानित 52 वेंट्री में परिकल्पित किया गया है और यह कि अधिसूचना दिनांक 13.5.1968 को जिसमें अपीलीकर्ता को धर्मदा कर लगाने और वसूल करने की अनुमति दी गई, वैध नहीं है, अनधिकृत, अस्वीकृत, अस्वीकृत, अव्यवस्थित और अस्थूल। इस कथन की स्वीकृति में, यह दावा किया गया कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ।। में किसी भी प्रविष्टि में धर्मदा कर लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है और राज्य विधायिका द्वारा बनाई गई किसी विशेष विधिकी अनुपस्थिति में, नगरपालिका द्वारा धर्मदा कर के लगाने का

हालांकि, पहले ही दर्शाया गया है कि विभागीय पीठ के निर्णय में, 1962 में जारी अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद उद्धरणित किया गया है, दिवस्तु के निर्माण के बारे में भी संदर्भ दिया गया है जिसमें उल्लिखित है कि 13.5.1968 को जारी अधिसूचना के तहत अपीलीकर्ता को आधिकारिक गजेट में उसके प्रकाशन की तारीख से उपयोग, सेवन और बिक्री के लिए वस्तुओं पर नगर शुल्क करने की अधिकारिता दी गई है और इससे संबंधित जोड़ी जगह 'धर्मदा' के निचे, विभिन्न वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है और 14 वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक ऐसे वर्ग में उन वस्तुओं के नामों के अलावा धर्मदा की दरें भी उनमें निर्दिष्ट की गई हैं। उत्तरदाता – वादी का एक आपत्तियों में यह भी दावा किया गया कि जिन वस्तुओं पर नगर शुल्क कर भुगतान करना है, उनी वस्तुओं पर धर्मदा कर दो विभिन्न नामों से लगाया नहीं जा सकता है नागरिक न्यायालय  के समक्ष अपीलीकर्ता द्वारा लिया गया एक निर्णय था कि धर्मदा नगर शुल्क लेवी से अलग नहीं है, बरुआ वही लेवी का एक अभिन्न हिस्सा है जिसका विशेष उद्देश्य और साथ ही नगर शुल्क के साथ वसूल किया जाता है और इसलिए यह अपीलीकर्ता के लिए विधायिक सूचना द्वारा अधिकार और योग्यता के भीतर था। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 277 पर भी भरोसा किया गया था, कोटा राज्य छुंगी अधिनियम, 1929 और राजस्थान नगरपालिकाएँ अधिनियम की धारा 2 पर आधारित रहा है जिसके तहत यह आधिकार व्यक्ति किया था।

मान्यवर न्यायिक न्यायाधीश ने अपने निर्णय और दिनांक 26.11.1979 के द्वारा यह ठान लिया कि धर्मदा लव्य भी नगर शुल्क है और इसे अधिनियम की धारा 104(2) के अंतर्गत न्यायित किया गया है। उत्तरजित होकर, उत्तरप्रदेश–कंपनियों ने जिला न्यायाधीश/12/80 में आपत्ति दाखिल की और कोटा के अतिरिक्त न्यायिक न्यायाधीश ने अपने 8.9.81 के निर्णय द्वारा न्यायिक न्यायाधीश के निर्णय की आपत्ति की स्वीकृति दी और यह आपत्ति खारिज कर दी। इसके पश्चात्, मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया। यद्यपि शिक्षित एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के एक विभाजनी पीठ के पूर्व निर्णय पर आश्रित किया, जिसका विषय C.A. संख्या 2994/1984 के रूप में है, और प्रत्यर्थी कंपनी की दावा को मान्य किया। इस चरण पर यह दिखाया जाता है कि विभाजनी पीठ ने केवल नगर शुल्क जैसे अनिवार्य करों से निपटने वाले धरावणा 104(2) का संबंध नहीं रखता था जैसे कि धर्मदा कर और इसलिए राज्य सरकार ने अपीलीकर्ता–नगरपालिका को कोटा के नगरपालिका की सीमाओं के भीतर माल लाने के लिए धर्मदा वसूल करने की अधिकारिता नहीं दी थी। हालांकि विभाजनी पीठ

ने कंपनी की दावा को स्थिर रखते हुए उसने न केवल अपीलीकर्ता को निरन्तर रूप से किसी भी धर्मदा कर लगाने और वसूल क।।।

फिर भी अनापत्ति के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया और यह दृढ़िकरण किया गया कि उत्तरदाता कंपनियों ने पहले से ही ग्राहक को धर्मदा कर दिया है, जिसे उन्होंने चुका दिया है, तो कंपनी को इसे रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और परिणामस्वरूप इसके बजाय कंपनी को जमा की गई राशियों की वापसी की निर्देशित की गई (छह महीने के भीतर) राजस्थान राज्य को एक और निर्देशन देते हुए कि इस राशि का कैसे उपयोग राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे परिस्थितियों में ये अपीलें इस सीमा न्यायालय द्वारा कोटा नगरपालिका की ओर से दायर की गई हैं।

श्री अल्ताफ अहमद, जिन्होंने अपीलकर्ता के रूप में उपस्थित होकर, कड़ी मेहनत से यत्न किया कि नामकरण चाहे जैसा भी हो, वास्तविक रूप से नगरपालिका की सीमाओं के भीतर आयात की जानेवाली सामग्री पर लगाने और वसूल करने की प्रक्रिया धर्मदा के शीर्षक के तहत एक 'नगर शुल्क' है, जो भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची के सूची ।। के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है और इस आदान–प्रदान के लिए किये गए विभिन्न नाम और/या लेबल के बावजूद लगाने के स्वरूप और स्वभाव में किसी भिन्नता नहीं दर्शाने या इसे वास्तविक नगर शुल्क से भिन्न या किसी विशिष्ट विषय में बदल देने के लिए नहीं है। इस लेवी के ऐतिहासिक उत्थान पर निर्भर करते हुए यह भी दावा किया जाता है कि धर्मदा से जुड़ी राशियों का विशेष रूप से निर्दिष्ट करना श्रीमान राजस्थान की गरीब और जरुरतमंद वर्ग को खिलाने, कपड़े पहनाने; शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता देने; गौशाला चालन करने और पशुओं को चारा प्रदान करने; भटकते हुए कुत्तों का ख्याल रखने; भटकते हुए कुत्तों का ख्याल रखने; अज्ञात लाशों की अंतिम यातायात करने; अंशधाल्य, धर्मशाला, पानी के झूले चलाने; गरीब लड़कों को पुस्तकें और गरीब लोगों को कपड़े और राजायन देने; विद्यालयों को सब्सिडी प्रदान करने; खेल आयोजित करने; अस्पतालों का विस्तार करने और उन्हें संचालित करने; और उपयुक्त करने के लिए व्यक्त किया गया था और बहुत सारी ऐसी दानवीय योजनाएँ और उद्देश्यों के लिए किया गया था। दावा किया जाता है कि इसलिए यह लेवी धर्मदा के रूप में किया गया था, हालांकि यह उत्तीर्ण करने के लिए खुला था और राज्य विधानमंडल और सरकार दोनों के अधिकारी थे कि ऐसे सभी उद्देश्यों के लिए नगर शुल्क श्रेणी के तहत लेवी और वसूल करने के लिए अधिकारी किया जाए।

अधिवक्ता  ने आगे यह भी दावा किया कि विशिष्ट लेवी को विधानिक विधियों द्वारा निर्धारित किसी भी विशेष प्रतिबंध या सीमा के अभाव में, राज्य को अपनी वित्तीय और बजटीय आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को उपयुक्त करने के लिए उसकी खुद की योजना, ढांचा, विधि या वित्तीय उपायों के वर्ग का निर्माण करने के लिए अधिक विशेष क्षेत्र और क्षमता है। जब तक, प्रथावधान में, लेवी नगर शुल्क के विशेष गुण को पूरा करती है, तो यह दावा किया जाता है कि नगर शुल्क को कैसे और किस रूप और तरीके से और किस उद्देश्य के लिए या नगर शुल्क या नगर शुल्क के विभागों का एकत्रित या अंश वसूल किया जाता है, यह राज्य के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह दावा किया जाता है कि सिद्धांत के रूप में किसी भी एक ही कर या उद्धारण पर दो या दो से अधिक कर या दरों का लगाना वैधानिक या अवैध और अवैध नहीं है और यह भी संवितानिक नहीं है, जब तक

इस तरह की सभी लेवी या दरों को साथ में या एक साथ लगाया नहीं जाता है या यह साबित या सिद्ध किया जाता है कि यह सन्दर्भित तथा तर्कशील नहीं है।

डॉ. एएम सिंघवी, सीए नंबर 4152/91 में एपेलेंट के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता , अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता ों के तर्कों को अपनाने के अलावा, ... पर विचार किया कि जब तक कर लगाने की वह अधिकारित उपाधि के तत्वों को पूरा करती है, यह अनुपूरक रहता है कि उसे किस नाम से बुलाया या पहचाना जाता है और कम से कम यह भी उद्देश्य है कि आरंभिक निर्णय के बाद कार्यवाही हुई और वहां जमा की गई रकम को वापस करने के लिए न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। विशेष रूप से जब संभावित है कि जिन उत्पादों की विनिर्मित और बेची गई मूल्य से उत्पन्न विनिर्माण कारख़ज़ आरक्षित की गई थी, वे उत्तरदाता–कंपनियों ने निश्चित रूप से उन्हें उपभोक्ताओं को दिया होगा। या तो उत्तरदाता कंपनियों को या सरकार को, विशेष रूप से जब सामान्य परिस्थितियों के अनुसार यह संभावित है कि उत्तरदाता कंपनियाँ निर्मित और बेचे गए उत्पादों के मूल्य के साथ इसे उपभोक्ताओं को देना होगा।

श्री शांति भूषण, उपाध्यक्ष अधिवक्ता  जो प्रतिस्पर्धी के द्वारा अपनाए गए तर्कों को समान उत्साह और बल से प्रस्तुत किया गया है, यह दावा करते हैं कि धर्मदा का नाम से कर लगाना विधिमें अज्ञात है और संविधान द्वारा राज्य विधायिका या सरकार द्वारा ऐसे कर की विधान करने के लिए कोई अधिकार नहीं है और इसलिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सही रूप से रद्द कर दिया गया है। यह भी दावा किया गया कि अधिनियम की धारा 104(2) राज्य सरकार को केवल उपकर का दर और दिनांक निर्धारित करने की अधिकारी है, अधिनियम और नियमों द्वारा प्रदत्त रीति में, और इसलिए धर्मदा को किसी भी रूप में उपकर के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, ऐसे कोई तर्क नहीं कर सकता। धर्मदा, यह दावा किया जाता है, एक अच्छी तरह पहचानी जानकारी है और जब सरकार द्वारा जारी एक समाचित अधिसूचना उपकर और धर्मदा के वियोजन को विधिपूर्वक निर्धारित करती है, तो उन्हें एक ही नहीं, बल्कि यह अलग लेवीज के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, यह भी दावा किया गया है कि नगर निगम द्वारा इस धन को विभिन्न उद्देश्यों के संदर्भ में लागू करना है जिन्हें धारा 98, 99, 101 और 102 में वर्णित किया गया है, और जुटायी गई राशि को केवल वही कर सकता है जिनके रूप में उपकर का तर्क किया जाता है। उत्तरदाताओं के लिए यह भी दावा किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को कर देने का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है और एक ऐसा उपकर जिसे अधिकृत और अवैध माना गया है, अगर यह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एकत्रित भी पाया जाता है,

इसको विधिकी जबरन करने के तहत जिसने यह देन किया है, उस व्यक्ति को वापस करना होगा। इस संदर्भ में इस महकमे के द्वारा सुनायी गई अंतरिम आदेशों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें अपीलकर्ता को कंपनियों से धर्मदा कर के आधे राशि की वसूली करने की अनुमति दी गई थी, उचित स्थितियों में उचित प्रावधान के साथ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के द्वारा वसूली गई राशि कंपनी को ब्याज पर 12% प्रति वर्ष के साथ वापस की जानी चाहिए। इसलिए, यह दावा किया गया है कि जब उनके दावों को अपील में हार हो और कोई भी युक्ति 'अनुचित अनुपूरक' या 'भविष्य की पूर्वानुमान' के सिद्धांत पर नहीं जोर दिया जा सकता।

भारतीय संविधान के अनुसार धारा 277 और 376 के आधार पर अपीलकर्ताओं का दावा करते समय, उसे कहा गया कि उन धाराओं का इन घटनाओं पर कोई संबंध या अनुप्रयोग नहीं होगा। उन्होंने ऐसा सिद्ध करने के लिए

न्यायिक उत्तरदाता, कमीशनर ऑफ इनकम टैक्स, (केंद्रीय) दिल्ली, नई दिल्ली बीजली कॉटन मिल्स (पी) लि। बीजली ने वायुयान, हाथरस, जिला अलीगढ़, [1979] 1 एससीसी 496, में दिखाया है, जिससे धर्मदा कर के वसूल और वसूल किया जाने की धर्मदा की स्वभाव और चरित्र की आधारित स्थिति को समर्थन किया गया है। हमने समय के साथ हमारे सम्माननिय अधिवक्ता ों के तर्कों को विचार किया है, जो हमारे विचार के लिए हमारे सामने रखे गए मामलों के प्रकाश में। इन अपीलों में विचार के लिए उपस्थित हुए प्रत्यार्पित अधिवक्ता ों के तर्कों की मुख्य मुद्दा यह है कि जिस वर्णन से लेवी करने और जमा करने का प्रयास किया जाता है जिसे धर्मदा

यदि उत्तर यह हो कि यह ऑक्ट्रॉय से किसी भी तरह अलग नहीं है और यह एक ही बात है, तो हमारे लिए इसे दो अलग प्रकार से देखने की अत्यआवश्यकता नहीं होगी।

अक्ट्रॉय के लेवी करने के आंशिक इतिहास को इस महकमे ने कई बार न्यायिक रूप से नोटिस किया है। बर्माह–शैल ऑयल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेलगाम बरो नगर पालिका, बेलगाम, AIR (1963) SC 906 में, इस महकमे की एक संविधान पीठ ने न केवल इस अवधारणा के उत्थान का पूरा विवरण किया बल्कि इसके विकास के पारंपरिक चरणों को भी संक्षेपित रूप से नोटिस किया, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह कैसे विधायिकी शक्ति के एंट्री 52 में सूचीबद्ध रूप से उल्लिखित हुआ।

विशेष कर वह 'नगर शुल्क ' था और कोई कर का विवरण नहीं था। शब्द 'नगर शुल्क ' शब्द 'ऑक्ट्रोये' से आता है जिसका अर्थ है 'देना', और इसका मौलिक उपयोग किसी वस्तु को शहर में लाने पर 'आयात' या 'शुल्क' या 'नगर शुल्क' का होता था। पहले 'नगर शुल्क ' को बंदरगाहों पर वस्तुओं का शुल्क वसूल किया जाता था लेकिन उन्हें उत्पन्नकरने के लिए नगर की सीमा को बदल दिया गया। ये 'नगर शुल्क' के रूप में जाने लगे। ये न केवल 'आयात' पर बल्कि 'निर्यात' पर भी वस्तुओं के शुल्क को वसूल करते थे। Beuhler: सार्वजनिक वित्त (तीसरा संस्करण) पृ. 426 में देखा जा सकता है। उनके राष्ट्रीय और स्थानीय वित्त पृ.303 में ग्राइस ने कहा कि वे 'इनगेट टोल्स' के रूप में जाने जाते थे क्योंकि वे टोल गेट्स या बैनियर्स पर वस्तुओं का शुल्क वसूल करते थे। आमतौर पर, ये उपभोक्ता के लिए उपयुक्त वस्तुओं पर लगाये जाते थे लेकिन सेलिगमैन के सामाजिक विज्ञानों के इंसाइक्लोपीडिया खण्ड IX पृ. 570 में, 'नगर शुल्क ' का वर्णन किया गया है बिना किसी उपयोग या सेवन के संदर्भ के। संपादक यह सार्वजनिक वित्त के लिए वर्णित करते हैं।

राष्ट्रीय सरकार की सुविधाओं की तुलना में स्थानीय निकायों के द्वारा राजस्व उठाने की संभावनाओं की सीमा बहुत सीमित है। सभी प्रकार के परोक्ष करों के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के पास वास्तविक रूप से कोई विकल्प नहीं है। उन्हें विपणन नग

यह देखा जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम में 'नगर शुल्क ' का उल्लेख था, लेकिन यह किसी विवरण द्वारा नहीं बताया गया था और अब संविधान 'नगर शुल्क ' शब्द से बचता है, जैसा कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी करता था, और एक विवरण देता है। नगर अधिनियम में 'नगर शुल्क ' की परिभाषा टर्मिनल कर शामिल है। भारतीय विधायिका समिशन बताती है कि पहले भारतीय वित्तीय शब्दकोश में टर्मिनल कर का अर्थ था जिसे रेलवे स्थलों पर लगाया गया था और स्टेशन से आयात या निर्यात की जाने वाली सभी सामग्री पर रेलवे प्रशासन द्वारा वसूल किया गया था। यह कुछ नगर पालिकाओं में यात्रियों से भी वसूला गया था। हम यह भी

सीखते हैं कि रिपोर्ट से कमेटी की सिफारिश पर 1908 में टर्मिनल कर ने पहले संघी राज्यों में और फिर अन्य जगहों में नगर शुल्क  की जगह ली। पहले भारत सरकार को ऐसा बदलाव करने के पक्ष में नहीं था नगर शुल्क उन वस्तुओं पर लगाई गई थी जो स्थानीय क्षेत्र में सेवन, उपयोग या बिक्री के लिए लाई गई थी और यह अप्रत्यक्ष कर थे, लेकिन टर्मिनल कर को सीधा करारा माना गया था। 1917 के 6 जुलाई को भारत सरकार ने एक संकल्प से अपने पूर्व नीति को बदल दिया और स्वीकार किया कि यह परिवर्तन अप्रत्यक्ष से सीधे कर नहीं था। टर्मिनल कर नगर शुल्क  के प्रकार के थे, लेकिन बिल्कुल समान नहीं थे। प्रमुख विभिन्नताएं थीं, जैसे कि टर्मिनल कर नियमों के तहत कोई वस्तु वापसी प्रणाली नहीं थी (टर्मिनल कर गैदे शिर्रास के अनुसार कभी–कभी 'वापसी के बिना नगर शुल्क ' के रूप में जाने जाते थे) और बिक्री, उपयोग या सेवन के लिए वस्त्राणित की जानी चाहिए।

शुल्क निर्धारण नियमों के बाद, टर्मिनल कर के वसूलन को वोह क्षेत्रों तक सीमित किया गया था जिनमें 1917 के 6 जुलाई के पहले या उसके बाद नगर शुल्क  लगाई गई थी। अधिकांश नगर व्यवस्थाओं ने केवल तब टर्मिनल कर के वसूलन को अनुमति दी यदि नगर शुल्क  लगाई नही गई थी। कर आय संदर्भ आयोग की टिप्पणी के अनुसार: (वॉल्यूम III चैप्टर IV पृष्ठ 401) "..... सबसे महत्वपूर्ण विभिन्नता नगर शुल्क  की विशेषता है कि इसके लिए यह कर लगाने के लिए विशिष्ट आवश्यकता है कि माल न केवल क्षेत्र में प्रवेश करें, बल्कि वहाँ उपयोग, उपयोग या बिक्री के उद्देश्य के लिए हों। सामान्यत: इस आवश्यकता को इस तरह से संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है (a) उन वस्तुओं की शुरुवाती मुक्ति जो केवल क्षेत्र से होकर जाती हैं, चाहे विच्छेद स्थानीय हो या एक अंतराल के बाद, या (b) इस प्रकार की वस्तुओं पर वसूल की गई कर की पुनःवसूली। इसलिए, छूट और पुनःवसूली, नगर शुल्क  प्रणाली की विशिष्टताएँ हैं।"

नगर शुल्क  और टर्मिनल कर अलग कर दिए गए थे हालांकि वे एक संदर्भ में समान थे, यह कि वे स्थानीय क्षेत्र में लाये जाने वाले वस्त्रों के लिए लगाए जाते थे। जबकि टर्मिनल कर को 'आयात या निर्यात' से जुड़ा हुआ माना जाता था कि वे सामग्री के यातायात से जुड़े थे, तो नगर शुल्क , उस समय लागू निर्धारण के अनुसार, उपयोग,

1935 के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था, तो टर्मिनल करें एक केंद्रीय विषय बन गए, सूची 1 के विषय सूची की आइटम संख्या 58, जिसमें निम्नलिखित लिखा था:–

"58. रेलवे या वायु मार्ग से ले जाए जाने वाले सामान या यात्रियों पर टर्मिनल करें।"

तब सर वॉल्टर लेटन ने सुझाया कि उन दोनों नगर शुल्क  और टर्मिनल करें को प्रांतीय विषय बनाया जाए और शायद यह संभव हो कि दोनों को एक साथ मिलाया जाए। संयुक्त समिति ने हालात कुछ और बताया और टर्मिनल करें को नगर शुल्क  से अलग कर दिया और उन्हें केंद्रीय सूची में शामिल कर दिया। टर्मिनल करें की आय, हालांकि, प्रांतों में वितरित की जाने वाली थी। 'नगर शुल्क ' को प्रांतों को आवंटित करते समय, शब्द खुद को तलिका में शामिल नहीं किया गया क्योंकि टर्मिनल करें भी एक अर्थ में नगर शुल्क  हैं और बजाय इसे

'स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश का करेंगी, उपयोग या बिक्री करें' की वर्णन किया गया था जो पहले ही उद्धित किया गया है, और जिसमें शब्द नया है "करों" कर दिया गया था जिसे नगर शुल्क के संदर्भ में उद्धाटित किया गया

प्रांतों को नगर शुल्क आवंटित करते समय, स्वयं शब्द को टाल दिया गया क्योंकि टर्मिनल करें भी एक अर्थ में नगर शुल्क हैं और इसके बजाय, कर का विवरण प्रविष्टि संख्या 49 में उद्धृत किया गया था, जिसे पहले से ही उद्धाटित किया गया था और जिसमें यह पढ़ा था "स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर करें, उपयोग या बिक्री करें"। यह योजना संविधान में पुनः प्रतिष्ठित की गई है, इसके भिन्नता यह है कि टर्मिनल कर द्वारा संबंधित प्रविष्टि अब "रेलवे, समुंदर या वायु मार्ग से ले जायी जानेवाली सामग्रियों और यात्रियों पर कर" पढ़ता है, और यथासम्भावित अर्थ में "करों" शब्द ने नगर शुल्क से संबंधित प्रविष्टि में "कर्यों" शब्द का स्थान लिया

इन दो करों का इतिहास स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जबकि टर्मिनल करें केवल स्थानीय क्षेत्र में सामग्री के प्रवेश के साथ संबंधित थे, चाहे वे उनका उपयोग वहाँ किया जाता हो या न हो।; नगर शुल्क सामग्री के प्रवेश के लिए कर थे जो संबंधित थे, उपयोग या बिक्री के लिए क्षेत्र में लाई जाती थी। वे सामग्री के उपयोग के लिए किसी न किसी उद्देश्य से क्षेत्र में लाई जाती थी, लेकिन केवल तब जब वे ऐसे उद्देश्य के लिए थीं। जब भारत सरकार अपने निरूपित कर नियमों में "नगर शुल्क " का उल्लेख करती है, तो इसका अभिप्राय इस प्रकार के करों को उल्लेखित करना था, अर्थात्, स्थानीय क्षेत्र में सामग्री के प्रवेश पर लगू होने वाला कर, उपयोग या बिक्री के लिए। ... "

इन मामलों में नगर शुल्क कर की आरोपण को खुद नहीं चुनौती दी गई है लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है कि जो 'धर्मदा' के रूप में व्याप्त किया जाता है और जो नगरपालिका परिषद इसे केवल नगर शुल्क का एक कर या धर्मदा के उद्देश्यों के लिए या धर्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वार्षिक कार्यक्रमों को आचरण करने के लिए परिसूचित किया जाता है जो धन्यवादी हैं कि धर्मदा को एक अलग और अलग कर रहे हैं कर, अनधिकृत, अधिकारित और वैधानिक नहीं है जिसका परिवारण संविधान की अधिनियमों, अधिनियम की धाराओं और अधिनियम के अनुसार तथा अधिनियम की धारा 104 (2) के तहत जारी अधिसूचना के अधीन नहीं है।

और उस नगर शुल्क के नाम से वस्त्रित अंतर्गत जानकारी और दृढ़ता से दर्ज करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तरदाता कंपनियों द्वारा उक्त आरोपण के खिलाफ कोई चुनौती नहीं है कि धर्मदा और निरखी का आरोपण और ऐसा जारी किया जाता है या अलग–अलग रूप से नगर शुल्क के रूप में आरोपित होने से उक्त आरोपण या तो उत्पन्न या तो असंतुलित हो जाता है, क्योंकि ऐसे मुद्दे संविधानिक वैधता के बारे में होते हैं जो सामान्य नागरिक न्यायालयों के सामने नहीं उठाए जा सकते हैं और वह भी एक केवल निष्कर्ष के रूप में, निर्दोषी या तो असंतुलित नहीं बनाते। भारतीय संविधान की सातवें अनुसूची के सूची–II के विषय 52 के अनुसार राज्य विधानसभाओं को वस्त्रित क्षेत्र में सामग्री के प्रवेश पर कर और उसका आकलन करने के लिए विधान प्रदान करने की अनुमति देती है, जो सामानय रूप से नगर शुल्क के रूप में जानी जाती है और/या स्थानीय प्राधिकरणों को उसे लगाने और जमा करने की अनुमति देती है। अधिनियम की धारा 104 (2) के अनुसार प्रत्येक नगर परिषद राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित करने पर केवल उत्तेजना का कार्य करने के लिए शुल्क लगा सकती है और ऐसे रेट और ऐसे तारीखों पर, जैसा कि सरकार अधिसूचित करती है, और उनके द्वारा तय किए जाने वाले तरीके

और नियमों के अनुसार सूचना के द्वारा उत्तरदाता से आयोजन करने की अनुमति देता है, स्थानीय क्षेत्र में वस्त्र और जानवर लाये गए। विधान के अनुसार वस्त्र कर की आरोपण व्याप्त नहीं किया गया था लेकिन वही वस्त्र कर बल्कि जनरल इंडिया एक्ट, 1935 में टर्मिनल करों को राजकीय विषय बना दिया गया, देखें सूची 1 के विषय 58 में निम्नलिखित रूप से: – "58. रेलवे या वायु मार्ग द्वारा बहाए जाने वाले माल या यात्रियों पर टर

धारा 104 के तहत चुकाया जाने वाला कर पूरे के पूरे रूप में 'अनिवार्य कर' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे सरकार द्वारा सूचित किया गया है, केवल तब नहीं लगाने का कर्तव्य है, जब उसे सरकार द्वारा सूचना के माध्यम से विशेष रूप से छूट दी गई हो, इस संबंध में उपयोग होने वाले पर्याय के तहत।

चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद रूप से विधान के अनुशासन द्वारा जारी अधिसूचना, वह अधिसूचना विविध वस्त्र और वस्त्र की श्रेणी और कर की दर की एक सूची प्रदान करती है जिसे नगर परिषद द्वारा लगाया जाने वाला कर विवरणित करती है। उस सूची में केवल 'अकट्रय' के रूप में कर लगाने की विशिष्टी दी गई है, बल्कि वहां शहरनामा धर्मदा और निरखी शहरनामा को भी लगाने की व्यवस्था की गई है, जब ऐसे वस्त्रों को नगरीय सीमाओं में लाया जाता है जो उपभोक्ति, उपयोग या वहाँ बिक्री के लिए नगर परिषद के कर्जाने का विवरण और वर्णन भी है और दरें भी हैं। धारा 104 (2) के अधीन जारी अधिसूचना के अभ्यास के तहत जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत एक विस्तारण की गई व्यवस्था दिखाई देती है कि कुछ वस्त्रों के वर्ग या वर्ग का एक अतिरिक्त लव और संग्रह की व्यवस्था प्रदान करने का उद्देश्य है, जो आमतौर पर इसके अधिभूत उद्देश्य या मांग के विशेष उद्देश्य या वस्तु का प्रमाण है लेकिन फिर भी केवल वे वस्त्र हैं जिन्हें नगरीय सीमाओं में प्रयुक्ति, उपयोग या वहाँ बिक्री के लिए लाया जाता है और वह भी एक अकट्रय के रूप में। यदि यह सही स्थिति है तो क्या इसे केवल एकल लेवी की अनुमति या दोहरा कर लेने के केवल कारण के रूप में उचित रूप से प।।।।।

जब कभी किसी कर के लगाये जाने की चुनौती की जाती है, तो उसकी वैधता का मुख्य रूप से इसे संबंधित विधायिका सक्षमता या शक्ति के संदर्भ में निर्धारित करना हो सकता है और इस विषय को निर्धारित करने में कर के स्वभाव और गुण को अपरिहार्य रूप से निर्धारित किया जाना होगा। यह भी निश्चित है कि एक बार तब कर लगाने की शक्ति विधायिका द्वारा होने का प्रमाण मिल गया है, तो उसके लगू होने का कारण अप्रासंगिक और अवास्तविक हो जाता है और यह भी कि वहां एक गलत कारण दिया जाता है कि कर का लगाने का अधिकार उपयोग किया गया है, तो ऐसा कुछ भी तरीके से उचित रूप से उचित नहीं होगा। 'उनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर व. मिस जुलुंदर रबर गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन' के मामले में, ए आई आर (1970) एससी 1589 में यह सुप्रीम कोर्ट ने 1947 में रबर एक्ट के धारा 12 (2) के तहत कर का उभयायन करने के खिलाफ एक चुनौती का मुखाय रूप से उद्घाटन किया कि कर उत्पादन या वस्त्र के उत्पादन पर बना रहता है। उसी तरह, एक बार यह तय हो जाता है कि विधायिका आवश्यक विधायिकी सक्षमता रखता है कि उसके द्वारा कर लगाने का विधिबनाने की क्षमता है, तो इसके बाद उस सक्षमता की सीमाएँ उस तरह से नहीं निर्धारित की जा सकती हैं कि उस शक्ति का उपयोग किस प्रकार से उचित रूप से किया गया है। मोरिस लेवेंथल और दूसरों वी. डेविड जोन्स, लिमिटेड, ए आई आर (1930) पी.सी. 129, में पूछा गया कि 'ब्रिज कर' लगाने की शक्ति क्या है, जबकि वास्तविक रूप से वस्तु था 'भूमि कर'। उसमें यह कहा गया था: "अपीलार्थी का दावा कि यद्यपि विधायिका द्वारा सीधे लगाया गया था, ब्रिज कर एक भूमि कर नहीं है,

"ब्रिज कर उधार दिया जाने का कोई ऐसा प्रमाणित कारण नहीं दिया गया था कि विधायिका द्वारा निर्धारित किया गया था, ब्रिज कर नई साउथ वेल्स के जीर्णमान रूप से पूरे क्षेत्र में नहीं बल्कि निर्दिष्ट अक्षम शिर्षों और विशिष्ट जिलों को शामिल करता है, और कर का उद्देश्य राज्य के सामान्य उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक राजस्व प्रदान करना नहीं है, बल्कि एक विशेष उत्थान योजना के लिए धन के निवेदन करना है। कोई प्राधान्य सर्वजनिक राजस्व उद्देश्यों के लिए यह कहने के लिए सफलतापूर्वक यह आरोपित नहीं किया गया है कि विधायिका द्वारा ध्वजित संपत्ति पर उपयोग किया गया कर किसी भी परिसीमित क्षेत्र के भीतर या निर्दिष्ट वर्गों की संपत्ति या निर्दिष्ट वर्गों के व्यक्तियों पर, उसे एक कर के वास्तविक अर्थ के भीतर नहीं गिना जाता है। न तो ऐसा कभी सफलतापूर्वक यह विपक्ष लिया गया है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए क़ानूनी उपहार द्वारा उठाया गया राजस्व उपकरण नहीं है।" [महत्वपूर्ण जोर दिया गया]

एक खण्ड पीठ ने 1962 में ए आई आर (1962) इलाहाबाद 83 में रिपोर्ट की गई एक निर्णय में, 'जलकर टैक्स' के रूप में लगाई गई उपहार की प्रकृति और विशेषता का विचार किया था, जब शक्ति थी कि 'इमारतों पर कर' लगाने की। डिवीजन पीठ ने AIR 1930 PC 129 के अनुपालन करते हुए यह तय किया:

"5. 'कर' एक ऐसा शुल्क है जो राज्य की विधायिकी शक्ति द्वारा व्यक्ति या संपत्ति पर लगाया जाता है ताकि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धन जुटाया जा सके। 'शुल्क' शब्द द्वारा प्रस्तुत सेवाओं के लिए पुनर्मुद्रिकरण का अर्थ है। इसमें शुल्क के मामले में 'क्विड प्रो क्वो' का तत्त्व होता है। जो इसे कर के मामले में नहीं है।"

मांगकर्ता के अधिवक्ता ने इस दिशा में इशारा किया कि धारा 129 की उपधारा (बी) के अनुसार, जलकर कर का उद्देश्य केवल नगरपालिका जल कार्यों के निर्माण, रखरखाव, विस्तार या सुधार से संबंधित व्यय को भुगतान करने के लिए है, और इससे प्राप्त सभी धन उक्त उद्देश्य पर ही खर्च किया जाएगा। उन्होंने यह दावा किया कि जलकर कर से जुटाए गए धन का केवल जल की आपूर्ति पर ही खर्च किया जाना, इसमें वस्तुत: द्विपक्षीय लाभ का तत्त्व है। यह विवाद ज्ञात नहीं लगता है। धारा 129 (ब) ने कर का उद्देश्य उल्लिखित किया है। क्योंकि नियमित जल आपूर्ति की रखरखाव और आपूर्ति को विस्तारित करना सबसे लाभकारी सार्वजनिक उद्देश्यों में से एक है, इसलिए धारा निर्धारित करती है कि इस प्रकार के कर से जुटाए गए धन का उपयोग जलकार्यों के निर्माण, रखरखाव और विस्तार में किया जाए ताकि धन की कमी के कारण उद्देश्य पर प्रभाव न हो। मोरिस) लेवेंथल बनाम डेविड जोन्स लिमिटेड, ए आई आर (1930) पीसी 129 में, न्यायिक समिति के उन उपाध्यक्षों ने यह तय किया कि किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विधिक रूप से लगाए गए आय का कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि यह कर नहीं था।

10. यह स्पष्ट है कि जलकर कर का विषय–वस्त्र जल नहीं है। हालांकि इसे जल शोध पर लगाया जाता है, इसे उसके उत्पादन पर नहीं लगाया जाता। न्यायिक समिति के उन्होंने –मद्रास प्रांत के न्यायलय बनाम गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ए आई आर (1945) पी.सी. 98 में स्पष्ट किया था कि यह उपकरण कर का नाम नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक प्रकृति, उसके 'मूल और सार' के रूप में जिसे कभी–कभी कहा गया है, जिससे यह निर्धारित हो कि यह किस श्रेणी में आता है।" [अत्यधिक बल दिया गया ]

हम उपर दी गई विधिकी वक्तव्य को सही मानते हैं और हमारे दृष्टिकोण में यह नामकरण जो कर लगाने के लिए चुकाने का चयन किया जाता है, यह वास्तविक विश्लेषण के लिए या उदाहरणार्थ, कर लगाने के वास्तविक स्वभाव और विशेषता या वास्तविक प्रकृति और विशेषता या लेवी के वास्तविक स्वभाव और चरित्र को निर्धारित करने के लिए आवश्यक है, शुल्क घटित होने का उल्लिखित होना नहीं है। हम रिकॉर्ड पर अविवादित तथ्यों पर विश्वास करते हैं कि 'धर्मदा' के रूप में लगाने की यातना केवल उस वस्तु के लिए है जो कोटा के नगरपालिका सीमाओं में उपभोग, उपयोग या वहां बिक्री के लिए लाई गई है, यह सच, वास्तविकता और सार में केवल एक 'नगर शुल्क ' है, जो कि सूची 98 और 99 में सूचीबद्ध उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है और अधिनियम की धाराओं 101 और 102 में व्यवस्थाओं के अनुसार आयोजित किए गए हैं। यह कि यह एक विभिन्न नाम से कहलाया जाता है (खासकर जब सप्तम कार्यक्रम की सूची–II के लिए विवरण 52 में 'नगर शुल्क ' शब्द स्वयं नहीं है) इतिहासिक कारणों और प्रशासनिक आवश्यकताओं या आवश्यकताओं के लिए केवल यह एक नाम होने का तथ्य, वास्तविक लेवी की प्रकृति और विशेषता को किसी भी प्रकार भी कमजोर नहीं करता है या सातवें अनुसूची की सूची–II के विवरण 52 के तहत एक ऐसे उपकरण का स्वरूप नहीं बनाता है या उसे इस सूची के तहत एंट्री 52 के तहत कोई कर नहीं बनाता है। विभिन्न दानी उद्देश्यों और सुधारात्मक योजनाओं और परियोजनाओं के लिए जो वर्गीकृत शिरोमणि के तहत वसूल हो रहे हैं, उन्हें अधिनियम की प्रावधानों के अनधिकृत या विधिके स्वीकृति के बिना कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई अनियमितता या अवैधता, यदि कोई भी व्यय के बाद शामिल है, तो यह न तो उस प्राधिकरण की क्षमता पर कोई प्रभाव डाल सकती है और न ही उसके वैधानिक योग्यता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जो कि उसके सांविधिक संविधानिक अधिकार के भीतर है और दिखाया नहीं गया है कि यह किसी भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। न तो उच्च न्यायालय ने व्यय किए गए कर के मामले में किसी ऐसे अवैधता के प्रश्न में प्रवेश किया है और न ही उसे सबूत करने के लिए हमारे सामने कोई विवरण है जिससे उत्तराधिकारी कंपनियों द्वारा इस संदर्भ में किसी ऐसे दावे की सत्यापनीयता को सिद्ध किया जा सकता है।

उचित वैधानिक आधार या पर्व इस तरह की उपयुक्ति नहीं है कि उच्च न्यायालय यह मान कर आगे बढ़े कि 'नगर शुल्क ' के रूप में लगू करने की अनुमति देना दोहरी कर करने की दोषी होगी और इसलिए विधिके अनुसार बुरी होगी, इस विषय में विधिकी यह स्थिर स्थिति की उपेक्षा की जा रही है। इस मामले में, इस सदन की संविधानिक पीठ ने 'मिस जैन ब्रदर्स और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य' मामले में निर्विवाद रूप से घोषित किया कि विधिके इस संदर्भ में स्थिति निम्नलिखित रूप से है:

यह विवादित नहीं है कि यदि विधायिका ने इसे स्पष्ट रूप से विधायित किया है तो दोहरा कर लगाना संभव है। यह केवल तब होता है जब कर लगाने के लिए सामान्य शब्द होते हैं और उन्हें विवरणित किया जाना है, तो उन्हें इस प्रकार विवरणित नहीं किया जा सकता कि विषय को एक ही कर के तहत दोहराया जाए (देखें चैनेल, जे, स्टीवेंस बनाम दरबान–रोडेपोर्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड, (1909) 5 टैक्स कैस 402)। संविधान में कोई भी प्रतिबंध नहीं है जो यह समझा जा सकता है कि एक निर्णय से ऐसा कर लगाना शामिल है जिसमें एक फर्म और उसके शारीरिक साथीयों को टैक्स करने की अवस्था है वर्णन के अनुसार अधीन संशोधन अधिनियम, 1956 के द्वारा। न ही किसी अन्य विधान है जो ऐसे कर को प्रतिषेधित करता है। यह सत्य है कि धारा 3 सामान्य लगानी धारा है। यदि धारा 23 (5) ने कर के लिए वस्त्र के संग्रह और पुनर्प्राप्ति के लिए योजना बनाई है,

तो संसद ने एक बार स्पष्ट शब्दों में संकेत किया है कि फर्म की आय को 1956 के वित्त अधिनियम के अनुसार कर लगाया जा सकता है और साथीयों की आय भी, तो एक लगानी और योजना धारा के बीच कोई भिन्नता कोई महत्व नहीं रखती। दोनों धाराएँ साथ में पढ़नी और समर्थन से विचार करनी हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की विधियों को 1961 के अधिनियम में भी अधिनित किया गया है। धाराएँ 182 और 183 धारा 23 (5) के लिए विपरीत हैं लेकिन पुराने धारा के पास धारा 182 के उपधारा (4) के तरह का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए, 1956 के बाद, पंजीकृत फर्मों के लिए जितने भुगतान करने के लिए है, वे खुद लगानी धारा के तहत मूल्यांकन करने के लिए और प्रत्यायेक शारीरिक साथी के हिस्से को उसकी कुल आय में शामिल करने के लिए हैं और उसके अनुसार कर लगाना। यदि कोई दोहरा कर लगाना शामिल है तो संसद ने स्पष्ट शब्दों में उसे अनुमति दे दी है। इसके बाद किसी को भी सामान्य सिद्धांतों को शामिल करन

अर्विंदर सिंघ आदि बनाम पंजाब और दूसरे मामले में, AIR (1979) SC 321, यह सीमा न्यायालय ने एक बार फिर निम्नलिखित रूप से रखा है:

"एक कमजोर यत्न कि दोहरा कर लगाने के दोष के कारण कर बुरा है और यह अव्यवस्थित है क्योंकि भारी पूर्व लेवीज़ हैं यह भी उच्चारित किया गया था। इनमें से कुछ तर्कों को ध्यान में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिवक्ता ों की शिष्टता के लिए उल्लिखित किया गया है। उदाहरण के लिए, आखिरी तरह से इसे ध्यान देते हैं। संविधान के अधिनियम 265 में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे दोहरा कर लगाने जैसा संवैधानिक दोष उत्पन्न हो सके। (खराब अर्थशास्त्र अच्छे विधिहो सकता है और उल्टा भी)। एक थोड़ी बहुत सीमित विवादित तर्क को देखते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पश्चिम भारत थिएटर्स, AIR (1954) बॉम. 261 में इसे त्वरित नकार दिया। कुछ ऐसे तर्क जिनके अधिकांश मूल्यांकन के योग्य नहीं हैं, लेकिन मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि एकांत में विश्रांति करें और पुनः जन्म न हों! यदि विधायिका एक ही विषय–वस्त्र पर कर लगाने का चयन करती है और उसे दो बार लगाने का निर्णय करती है, तो उसमें वित्तीय उपानुयायिता में कोई औचित्यिक अवैधता नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ कोई और प्रतिबंध हो।"

स्री कृष्ण दास बनाम टाउन एरिया समिति, चिरगांव मामले [1990] 3 SCC 645 और राधाकिशन राठी बनाम अतिरिक्त सहायक संग्रहक, दुर्ग और अन्य, [1995] 4 SCC 309 में यही स्थिति पुनः दोहराई गई है।

हालांकि एक ही वस्तु की विभिन्न नामों से कर लगाना आमतौर पर 'दोहरा कर लगाना' है, इस विषय की विशेषज्ञता के व्याख्यान से यह भी प्रतित होता है कि राजस्व के पक्ष में झुकाव है, क्योंकि विधायिका को एक या एक से अधिक कर या करों को लगाने और वस्तु के उधारण और वसूली का तरीका या प्रकार का चयन करने की यहां तक कि इन क्षेत्रों में विभिन्नता और व्यापक विवेक हमेशा राज्य को दी गई है, तो यदि संविधान या संसद द्वारा अक्षमता नहीं है और यह बात विधायिका द्वारा स्वयं रोकती है तो किसी दोहरा कर लगाने को दोषित माना जा सकता है। जहां विभिन्न विधायन या अधिकारों द्वारा कर लगाए जाते हैं या जहां दो में से केवल एक कर है या जहां यह पूरी तरह से विभिन्न उद्देश्यों के लिए है या जब यह सीधे स्थानिक बजट कर रही है बजाय प्रत्यक्ष, वहां कोई भी दोहरा कर लगाने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी विशेष रूप से विरुद्धता की कोई बाधा न होने पर एक देश के संविधान या संसद द्वारा स्थापित निर्देशिका की आवश्यकता या जरूरत राज्य के लोकनीति निर्माण और सार्वजनिक वित्तों को समायोजित करने के क्षेत्रों से संबंधित है, और न कि विधिकोर्टों के

लिए, हालांकि अगर एकांत से अधिक लगानियों के पक्ष में स्पष्ट और विशिष्ट आदेश न हो, तो सामान्य विधायिक धाराओं को व्याख्या करने के लिए एक व्याख्या की दिशा में झुक सकते हैं जो दोहरा कर लगाने के कारण किसी भी लवायल मना किया जा सकता है। ये हैं वे सिद्धांत या विधिके वक्तव्य।

अब हम इस मामले की तथ्य और परिस्थितियों पर आते हैं, हम यह पाते हैं कि यह कर निश्चित, स्पष्ट और सकारात्मक शब्दों में है, जिसमें एक निश्चित घोषित उद्देश्य शामिल है, जिससे किसी भी संदेह या उन संदेहों को दूर करने के लिए कोई अभ्यास नहीं बचता है। हमने 13.5.1968 को प्रकाशित गज़ेट में वेरनेक्यूलर में मौलिक सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, जो उपर सूचित किया गया है, और हम यह देखते हैं कि चुनौती में आने वाले लवायल की दरें एक ही व उसी अधिसूचना की एक और समारूप हिस्सा के रूप में अधिसूचित की गई हैं और उन्होंने किसी भी विभिन्न या एक से अधिक अधिसूचना द्वारा या किसी भिन्न अवस्था या समय पर नहीं। हालांकि यह देखा जाता है कि विभिन्न इनट्रीज में सूचीबद्ध कुछ आइटम या वस्त्र, जिनमें विभिन्न शीर्षकों के तहत धर्मदा शामिल हैं, वे केवल यथार्थ या पूर्णतः यातायातिक पुनरावृत्तियाँ नहीं हैं, उन्हें उनकी वर्गीकरण, सूचीकरण या दरों का निर्धारण देखते हुए नहीं। इसलिए, इन वस्त्र/सामग्रियों के कुछ या अन्य के संबंध में दरों की विविधता की विवरणित कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपने आप को 'दोहरा कर लगाना' के रूप में ठहराने या दंडित करने के लिए। विचार में आने वाले अधिसूचना को हमारी दृष्टि से किसी भी दोहरा कर लगाने के प्रयोग का हिस्सा माना जा सकता है और उच्च न्यायालय ने ऐसी एक त्रुटिपूर्ण परिस्थिति पर आधारित विचार में जाकर धर्मदा के उद्देश्यों के लिए कर लगाने को बुरा और अवैध घोषित कर दिया है।

ऊपर उल्लिखित सभी कारणों के आधार पर, ये अपील स्वीकार की जाती है और अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय का निर्णय जिनमें प्रत्यर्थी कंपनियों की दावे को नियमन और रिफंड करने की अनुमति दी गई, को निरस्त किया जाता हैं। प्रत्यर्थी कंपनियों द्वारा दायर की गई वाद को निरस्त किया जाता है। लेकिन मामले की परिस्थितियों में, वाद के खर्चों से संबंधित कोई आदेश नहीं होगा।

वी.एस.एस. अपील स्वीकार की जाती है।

*This is word to word true vetting/validation of the judgments done by Hina Kousar, 4th Additional Civil Judge (JD)*